



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 307] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 21, 2017/कार्तिक 30, 1939
No. 307] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 21, 2017/ KARTIKA 30, 1939

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 2017

(निर्णायक समीक्षा)

मामला सं. एसएसआर 16/2017

सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमरीका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कास्टिक सोडा के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा की शुरुआत

फा. सं. 7/16/2017-डीजीएडी.—यतः वर्तमान याचिका मै. अल्कली मेन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एएमएआई) द्वारा भारतीय उत्पादकों की ओर से दायर की गई है। याचिकाकर्ता एसोसिएशन ने सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमरीका (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) से कास्टिक सोडा (जिसे आगे संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों पर मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की अवधि बढ़ाने, उसमें संशोधन करने और वृद्धि करने के लिए 3 उत्पादकों अर्थात् डीसीडब्लू लि., ग्रासिम इंडस्ट्रीज लि. और एसआईईएल कैमिकल काम्प्लैक्स, द्वारा संगत वित्तीय सूचना उपलब्ध कराते हुए यह आवेदन दायर किया है।

पृष्ठभूमि

2. यतः प्राधिकारी द्वारा संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित मूल जाँच दिनांक 26 मई, 2000 की अधिसूचना 56/1/99-डीजीएडी द्वारा शुरू की गई थी और प्राधिकारी द्वारा अंतिम जाँच परिणाम 14 मई, 2001 की अधिसूचना सं 56/1/99-डीजीएडी द्वारा अधिसूचित किए गए थे। तदनुसार, दिनांक 26 जून, 2001 को शुल्क लगाते हुए सीमाशुल्क अधिसूचना सं 69/2011-सीमाशुल्क (एडीडी) जारी किया गया था। आरंभ में लगाये गए पाटनरोधी शुल्क को दिनांक 1 अगस्त, 2006 की अधिसूचना सं. 15/29/2004-डीजीएडी

द्वारा निर्णायक समीक्षा के अधीन नवीकृत किया गया और दिनांक 13 सितंबर, 2006 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 98/2006 द्वारा अधिसूचित किया गया।

3. पांच वर्ष पूरे होने पर, निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा 2 सितंबर, 2011 की अधिसूचना सं 15/28/2010 द्वारा सऊदी अरब, यूएसए, जापान, ईरान और फ्रांस से कास्टिक सोडा के आयातों के विरुद्ध निर्णायक समीक्षा जाँच शुरू की गई थी। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 31 अगस्त, 2012 की अधिसूचना 15/28/2010-डीजीएडी द्वारा यह सिफारिश की कि सऊदी अरब, ईरान, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका से आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क को जारी रखा जाए परंतु फ्रांस से आयातों के विरुद्ध नहीं। तथापि, जापान से आयातों के विरुद्ध निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा 'शून्य' शुल्क लगाने की सिफारिश की गई क्योंकि जापान से आयातों के संबंध में परिकलित क्षति मार्जिन ऋणात्मक था। दिनांक 26 नवंबर, 2012 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 49/2012-सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क को 5 वर्षों की अवधि के लिए आगे और बढ़ाया गया।

4. संयुक्त राज्य अमेरिका, ईरान और सऊदी अरब से आयात के खिलाफ प्राधिकरण द्वारा 22/1/2015 की अधिसूचना, दिनांक 22 जनवरी, 2016 को एक और मध्य-अवधि की समीक्षा शुरू की गई थी। नियुक्त प्राधिकरण ने तीन विषय देशों, जैसे सऊदी अरब, ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंध में विस्तृत जांच की; और सिफारिशों को अधिसूचना सं. 15/19/2015 दिनांक 20 जून, 2017 के माध्यम से जारी किया गया था। प्राधिकरण ने कर्तव्यों में संशोधनों की सिफारिश की थी जिन्हें अधिसूचना अधिसूचना संख्या 39/2017-सीमा शुल्क (ADD), दिनांक 23 अगस्त, 2017 के तहत अधिसूचित किया गया था।

शामिल देश

5. याचिका में विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाओं और तथ्यों की जांच के बाद प्राधिकरण ने सऊदी अरब और अमेरिका के खिलाफ जांच शुरू करने का फैसला किया है और डंपिंग और उनके खिलाफ चोट के पर्याप्त सबूतों की कमी के कारण जापान और ईरान के खिलाफ जांच शुरू नहीं की है। इसलिए, वर्तमान समीक्षा जांच में शामिल देशों में सऊदी अरब और अमेरिका हैं।

विचाराधीन उत्पाद

6. वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद सोडियम हाइड्रॉक्साइड (रासायनिक नाम एनएओएच) है, जिसे आम तौर पर कास्टिक सोडा के रूप में जाना जाता है (वर्तमान जाँच में कास्टिक सोडा भी कहा गया है)। विचाराधीन उत्पाद मूल जाँच में विचार किए गए उत्पाद के समान है।

7. कास्टिक सोडा एक अकार्बनिक, साबुनी, अधिक अल्कलाइन गंधरहित रसायन होता है और इसका प्रयोग पल्प और कागज, अखबारी कागज, विस्कोस यार्न, स्टेपल फाइबर, एल्युमिनियम, कपास, वस्त्र, प्रसाधन और लाउंड्री साबुन, डिटरजेंट, डाईस्टफ, औषध और भेषज, पेट्रोलियम शोधन आदि के विनिर्माण में होता है। कास्टिक सोडा को तीन प्रौद्योगिकीय प्रक्रियाओं अर्थात् मरकरी सेल प्रक्रिया, डायफ्रेगम प्रक्रिया और मेम्ब्रेन प्रक्रिया द्वारा दो रूपों अर्थात् लाई और ठोस रूप में उत्पादित किया जाता है। इन प्रक्रियाओं में अंतर से विभिन्न विशेषताओं के अनुसार उत्पाद में कोई अंतर नहीं होता है।

8. कास्टिक सोडा को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 28 के अंतर्गत सीमाशुल्क शीर्ष 2815 11 और 281512 के अधीन वर्गीकृत किया जाता है। आईटीसी 8-अंकीय वर्गीकरण के अनुसार, इस उत्पाद को सीमाशुल्क शीर्ष 2815 11 10, 2815 11 90 और 2815 12 00 के तहत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि उक्त वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जाँच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

समान वस्तु

9. समान वस्तु के संबंध में नियम 2(घ) में निम्नानुसार व्यवस्था है:-

“समान वस्तु” से ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जो भारत में पाटन के कारण जांच के अंतर्गत वस्तु के सभी प्रकार से समरूप या समान है अथवा ऐसी वस्तु के न होने पर अन्य वस्तु जोकि यद्यपि सभी प्रकार से समनुरूप नहीं है परंतु जांचाधीन वस्तुओं के अत्यधिक सदृश विशेषताएं रखती हैं;

10. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि संबद्ध देशों से निर्यातित और भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। इन दोनों उत्पादों में भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण जैसे मापदंडों की दृष्टि से तुलनीय विशेषताएं हैं।

घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

11. यह याचिका मै. अल्कली मेन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एएमएआई) द्वारा संबद्ध वस्तु के 3 प्रमुख उत्पादकों अर्थात् डीसीडब्लू लि., ग्रासिम इंडस्ट्रीज लि. और एसआईईएल कैमिकल काम्प्लैक्स की ओर से दायर की गई है। मै. ग्रासिम इंडस्ट्रीज ने 6 विनिर्माण इकाइयों के आकड़े प्रस्तुत किए हैं। यह बताया गया है कि याचिकाकर्ताओं का उत्पादन देश में संबद्ध वस्तु के भारतीय उत्पादन का 25.06 प्रतिशत है। आवेदकों द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ताओं ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है। अतः प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 2 (ख) के अर्थ के भीतर याचिकाकर्ता कंपनी को घरेलू उद्योग माना है और आवेदन संबंधित नियमावली के नियम 5 के अनुसार योग्यता संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

निर्णायक समीक्षा की शुरुआत

12. प्रस्तुत किए गए विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन को ध्यान में रखते हुए और पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 क(5) के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा निर्णायक समीक्षा जाँच की शुरुआत करते हैं ताकि समीक्षा की जा सके कि क्या संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में लागू शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा की जा सके और इस बात की जाँच की जा सके कि क्या लागू शुल्क को हटाये जाने से पाटन के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

जांच अवधि

13. आवेदक द्वारा जाँच अवधि (पीओआई) के रूप में अप्रैल 2016 से मार्च, 2017 और क्षति जाँच अवधि का अप्रैल 2013 – मार्च, 2014, अप्रैल 2014 – मार्च, 2015, अप्रैल 2015 – मार्च, 2016 के रूप में प्रस्ताव किया गया है। तथापि अधिक अद्यतन आकड़ों पर अपेक्षित विश्लेषण करने में प्राधिकारी को सक्षम बनाने के लिए, प्राधिकारी ने अप्रैल, 2016 से जून, 2017 (15 महीने) को पीओआई के रूप में एतद्वारा निर्धारित किया है। तथापि क्षति जाँच अवधि में 2013-14, 2014-15, 2015-16 और जाँच अवधि शामिल होगी। पाटन और क्षति की संभावना निर्धारित करने के लिए पीओआई से आगे के आकड़ों की भी जाँच की जा सकती है।

प्रक्रिया

14. इस समीक्षा में दिनांक 31 अगस्त, 2012 की अधिसूचना सं 15/28/2010-डीजीएडी और दिनांक 20 जून, 2017 की अधिसूचना सं 15/19/2015-डीजीएडी के अधीन यथा अधिसूचित सभी पहलू शामिल होंगे।

15. संबंधित नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के उपबंध आवश्यक संशोधनों के साथ इस समीक्षा पर लागू होंगे।

16. प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करते समय, संबद्ध देश में उत्पादक/निर्यातक को विनिर्माण, उत्पादन और घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की बिक्री और भारत और अन्य देशों को निर्यात के संबंध में बाजार दशाओं की मौजूदगी को प्रदर्शित करना होगा। इस प्रयोजनार्थ, उत्पादक/निर्यातक निम्नलिखित के संबंध में पर्याप्त सूचना उपलब्ध करा सकते हैं:

- क. कीमत, लागत, कच्ची सामग्री सहित निविष्टि, प्रौद्योगिकी और श्रम की लागत, उत्पादन, बिक्री और निवेश के संबंध में निर्णय बाजार संकेतकों जो आपूर्ति और मांग को दर्शाते हैं और राज्य के किसी हस्तक्षेप के बिना लिये जाते हैं और क्या प्रमुख निविष्टियों की लागत बाजार मूल्य को पर्याप्त रूप से प्रदर्शित करती है।
- ख. उत्पादन लागत और वित्तीय स्थिति किसी विकृति से प्रभावित नहीं हैं।
- ग. उत्पादक/निर्यातक दिवालिया और संपत्ति कानून के अधीन हैं जो फर्मों के प्रचालन के लिए विधिक निश्चितता और स्थिरता की गारंटी देते हैं।
- घ. विनिमय दर में परिवर्तन बाजार दर पर किये जाते हैं।

सूचना प्रस्तुत करना

17. संबद्ध देश में निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देश की सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु के आयातकों व प्रयोक्ताओं को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना निम्नलिखित को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है:

भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,

5 संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001

18. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत सूचना नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य पक्षों को उसे उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश भी प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

समय-सीमा

19. वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई के लिए कोई अनुरोध इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, रिकार्ड में "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

20. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस जाँच की शुरुआत की तारीख से 40 दिनों के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा पाटनरोधी उपायों को जारी रखने की जरूरत या अन्यथा के संबंध में घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

21. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के संबंध में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो ऐसे मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट (क) गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि); और (ख). अगोपनीय रूप में अंतिम दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) प्रस्तुत करना होगा। दी गई समस्त सूचना पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय "या" अगोपनीय" अंकित होना चाहिए और उनके साथ साफ्ट प्रति भी होनी चाहिए।

22. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। समस्त हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय रूपांतरण की दो (2) प्रतियां और अगोपनीय रूपांतरण की दो (2) प्रतियां प्रस्तुत की जानी चाहिए।

23. गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है और/या ऐसी सूचना का सारांशकरण क्यों संभव नहीं है।

24. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध / रिक्त छोड़ी गई और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

25. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

26. किसी सार्वजनिक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

27. नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

असहयोग

28. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 20th November, 2017

(Sunset Review)

Case No. SSR 16/2017

Initiation of Sunset Review of Anti-dumping Duty imposed on imports of Caustic Soda originating in or exported from Saudi Arabia and the United States of America.

F. No. 7/16/2017-DGAD.—Whereas, the present petition has been filed by M/s Alkali Manufacturers' Association of India (AMAI) on behalf of India producers. The petitioner Association have provided relevant financial information, by domestic producers namely DCW Limited, Grasim Industries Limited and SIEL Chemical Complex, to file this application for the extension of period, modification and enhancement of existing anti-dumping duties on imports of Caustic Soda (hereinafter referred to as subject good) from Iran, Japan, Saudi Arabia and the United States of America (hereinafter referred to as subject countries).

BACKGROUND

- Whereas, the original investigation concerning imports of the subject goods from the subject countries was initiated by the Authority vide Notification 56/1/99-DGAD, dated 26th May, 2000 and the final finding was notified by the Authority vide Notification No. 56/1/99-DGAD dated 14th May, 2001. Accordingly, Customs Notification No. 69/2011-Customs (ADD) dated 26th June, 2001 was issued imposing duty. The anti-dumping duty initially levied was renewed under sunset review vide Notification No. 15/29/2004-DGAD dated 1st August, 2006 and notified vide Customs Notification No. 98/2006 dated 13th September, 2006.
- Upon completion of five years, a Sunset Review investigation was initiated by the Designated Authority against the imports of Caustic Soda from Saudi Arabia, USA, Japan, Iran and France vide notification 15/28/2010 dated 2nd September, 2011. The Designated Authority vide notification 15/28/2010-DGAD dated 31st August, 2012 recommended continuation of anti-dumping duties against imports from Saudi Arabia, Iran and USA. The ADD against imports from Japan was recommended as Nil and ADD against imports from France was terminated. Accordingly, a customs Notification No. 49/2012 – Customs (ADD), dated 26th November, 2012 was issued valid for a period of 5 years.

4. Another mid-term review was initiated by the Authority vide notification 15/19/2015 dated 22nd January, 2016, against the imports from USA, Iran and Saudi Arabia. The Designated Authority conducted detailed investigations in respect of three subject countries, i.e. Saudi Arabia, Iran and USA; and recommendations were issued vide notification No. 15/19/2015 dated 20th June, 2017. The Authority recommended modifications in duty which were notified vide customs notification no. 39/2017-Customs (ADD) dated 23rd August, 2017.

Subject Countries

5. After due examination of various vital information and facts in the petition the Authority has decided to initiate the investigation only against Saudi Arabia and USA and not initiate the investigation against Japan and Iran in view of lack of sufficient evidence of dumping and injury against them. Therefore, the countries involved in the present review investigation are Saudi Arabia and USA.

Product under Consideration

6. The product under consideration in the present investigation is Sodium Hydroxide (chemical nomenclature NaOH), commonly known as Caustic Soda (referred to as caustic soda in the present investigation). The product under consideration is the same as considered in the original investigation.
7. Caustic soda is an inorganic, soapy, strongly alkaline and odourless chemical and finds application in various fields like manufacture of pulp and paper, newsprint, viscose yarn, staple fibre, aluminum, cotton, textiles, toilet and laundry soaps, detergent, dyestuffs, drugs and pharmaceuticals, petroleum refining etc. Caustic soda is produced in two forms, i.e., lye and solids by three technological processes, i.e., mercury cell process, diaphragm process and membrane process. The difference in these processes does not lead to a difference in product in terms of various characteristics.
8. Caustic soda is classified under Chapter 28 of the Customs Tariff Act, 1975 under Customs heading 2815 11 and 2815 12. As per ITC eight digit classifications, the product is classified under the Customs Heading 2815 11 10, 2815 11 90 and 2815 12 00. The classification is however, indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

Like Article

9. Rule 2(d) with regard to like article provides as under: -

"like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation;

10. Petitioner has claimed that there is no known difference in subject goods exported from subject countries and that produced by the Indian industry. Both the products have comparable characteristics in terms of parameters such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification, etc.

Domestic Industry & Standing

11. The petition has been filed by M/s Alkali Manufacturers' Association of India (AMAI) on behalf of 3 major producers of the subject goods i.e. DCW Limited, Grasim Industries Limited and SIEL Chemical Complex. M/s Grasim Industries has given data of 6 manufacturing units. It has been stated that the production of petitioner companies is 25.06% of Indian production of the subject goods in the Countries. On the basis of information furnished, the Authority notes that the petitioner companies have not made any imports of the subject goods from the subject country during the POI. Therefore, the Authority has considered the petitioner company as Domestic Industry within the meaning of the Rule 2(b) of the Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 of the Rules supra.

Initiation of Sunset Review

12. WHEREAS, in view of the duly substantiated application filed and in accordance with Section 9 A (5) of the Act, read with Rule 23 of the Anti-dumping Rules, the Authority hereby initiates a Sunset review investigation to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject countries and to examine whether the expiry of existing duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the Domestic Industry.

Period of Investigation

13. The period of investigation (POI) proposed by the applicant was from April, 2016 – March, 2017 and the injury investigation period was for the periods April 2013-March 2014, April 2014 to March 2015, April 2015 to March 2016. However, for enabling the Authority to make required analysis on the basis of more updated data, the Authority hereby determines the POI as April 2016 to June 2017 (15 Months). The injury investigation period will be the same i.e. 2013-14, 2014-15, 2015-16 and POI. The data beyond POI will also be examined to determine the likelihood of dumping and injury.

Procedure

14. The review will cover all aspects as notified under Notification No. 15/28/2010-DGAD dated 31st August, 2012 and 15/19/2015 dated 20th June, 2017.
15. The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 of the Rules supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.
16. While submitting questionnaire response, producer/ exporter may have to demonstrate prevalence of market condition related to manufacture, production and sale of subject good in the domestic market and in export to India and other countries. For this purpose, the producer/exporter, may clarify and provide sufficient information on the following:
 - a) Decision in regard to price, cost, input including raw material, cost of technology and labour, output, sales and investment, are made in response to market signal reflecting supply and demand and without significant state interference and weather cost of major inputs substantially reflect market value.
 - b) Production costs and financial situation does not suffer from any distortion.
 - c) The producer/exporter are subject to bankruptcy and property law which guarantees legal certainty and stability for the operation of the firms.
 - d) Exchange rate conversions are carried out at the market rate.

Submission of Information

17. The known exporters in the subject country, the Government of the subject country through its embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

Government of India
Ministry of Commerce and Industry
Department of Commerce
Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties
4th Floor, Jeevan Tara Building
5, Parliament Street, New Delhi – 110001

18. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to submit a non-confidential version of the same to be made available to the other parties.

Time Limit

19. Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-dumping Rules.
20. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the Domestic Industry's application regarding the need to continue or otherwise the Anti-dumping measures within 40 days from the date of initiation of this investigation.

Submission of information on confidential basis

21. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire response/ submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non- Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page and accompanied with soft copies.
22. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the

confidential version and two (02) copies of the non-confidential version must be submitted by all the interested parties.

23. For information claimed as confidential, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.
24. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out /summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
25. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
26. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of public file

27. In terms of rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidences submitted by other interested parties.

Non-cooperation

28. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. and Designated Authority